(2) 15 per cent for all ports beyond Cochin.

(b) The overall cost of transport of coal by the sea route will undoubtedly increase. The consumer, however, will not be affected as he will be given a subsidy almost equivalent to the difference between the freight by the *rail-cum-sea* route and the all-rail route. This subsidy is met from the excise duty levied on coal and coke and the consequence of the increase in shipping freight would be a larger outgo from the proceeds of the said excise duty.

Oil Refineries

*189. **Shri Vidya Charan Shukla:**
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **Mines and Fuel** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 588 on the 25th August, 1962 and state:

(a) whether a decision has been taken on the proposals made by Private Sector Oil Companies for utilization of the excess capacity available with their Refineries processing imported crude: and

(b) if so, particulars thereof?

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): (a) Yes, Sir.

(b) They have been temporarily permitted to operate at the maximum capacities available.

Vocational Training in Schools

*190. **Shri Warior:**
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have supplied machinery to schools in various States for vocational training; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

*१९१. **श्री भक्त दर्शन:** क्या शिक्षा मंत्री २५ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के चार राज्य-विश्वविद्यालयों पंत, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम जारी करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उस के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त विश्वविद्यालयों में कब तक उस के लागू हो जाने की आशा की जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति की नियुक्ति की है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे । दीवान आनन्द कुमार, सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्री प्रेम कृपाल, सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि, श्री सेमुअल मथाई, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डा० पी० जे० फिलिप, विकास अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके सदस्य होंगे । यह समिति उत्तर प्रदेश के चार राज्य विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को लागू करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता के संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के विस्तृत वित्तीय प्रस्तावों पर विचार करेगी ।

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह भी सूचित किया है कि उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम और उस के पश्चात् त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने के प्रश्न की जांच करने के लिये राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है